



2026:AHC:127216

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी सं - 22926 वर्ष 2026

श्रीमती निकिता दिवाकर और एक अन्य..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य..... प्रतिपक्षी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : संतोष कुमार गुप्ता

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता : मुख्य शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 49

माननीय न्यायमूर्ति श्री कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता और राज्य प्रतिपक्षियों के स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. प्रस्तुत रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ताओं ने परमादेश की प्रकृति में एक रिट के लिए प्रार्थना की है जिसमें प्रतिपक्षियों को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने और सुरक्षा प्रदान करने के निर्देश के लिए भी आदेश दिया गया है।
3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता संख्या-1 की आयु लगभग 26 वर्ष है और याचिकाकर्ता संख्या-2 की आयु लगभग 29 वर्ष है और दोनों उच्च स्कूल प्रमाणपत्र के अनुसार प्रमुख हैं। द ग्रेट आर्य समाज मंदिर ट्रस्ट, प्रयागराज द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र को संलग्न किया गया है और ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भी संलग्न किया गया है।
4. लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2006 क्रि.ल. 3309 में, अंतरजातीय विवाह करने वाले लड़के और लड़की के माता-पिता द्वारा उत्पीड़न के मामले से निपटते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर में प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित शर्तों में निर्देश जारी किए हैं: -

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



‘यह एक स्वतंत्र और लोकतांत्रिक देश है और एक बार जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है तो वह अपनी पसंद के किसी व्यक्ति से भी शादी कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता इस तरह के अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं, तो वे अधिकतम यह कर सकते हैं कि वे बेटे या बेटों के साथ सामाजिक संबंधों को तोड़ सकते हैं, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते हैं या हिंसा के कृत्यों को नहीं कर सकते हैं या उकसा नहीं सकते हैं और इस तरह के अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह से गुजरने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते हैं। इसलिए, हम निर्देश देते हैं कि पूरे देश में प्रशासन/पुलिस अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की जो एक वयस्क महिला या पुरुष के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है, जो एक बालिग है, तो दंपति को किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जाता है और न ही धमकी या हिंसा के कृत्यों के अधीन किया जायेगा, और कोई भी व्यक्ति जो इस तरह की धमकी देता है या परेशान करता है या हिंसा के कार्य करता है, ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध पुलिस द्वारा आपराधिक कार्यवाही शुरू करके कार्रवाई की जाती है और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानून द्वारा उपबंधित कड़ी कार्रवाई की जाती है।

5. भगवान दास बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2011) 6 एस.सी.सी.396
माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर-28 और 29 में निम्नानुसार निर्णय लिया: -

"28. अक्सर प्यार में पड़ने वाले युवा जोड़ों को कंगारू (स्वयंभू) अदालतों के क्रोध से बचने के लिए पुलिस लाइनों या सुरक्षा गृहों में शरण लेनी पड़ती है। हमने लता सिंह मामले में कहा है कि 'ऑनर किलिंग' में कुछ भी 'सम्मानजनक' नहीं है, और वे और कुछ नहीं बल्कि सामंती दिमाग वाले कट्टरपंथी लोगों द्वारा बर्बर और क्रूर हत्याएं हैं। हमारी राय में ऑनर किलिंग, चाहे किसी भी कारण से, मौत की सजा के लायक दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आती है। अब समय आ गया है कि इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को खत्म किया जाए जो हमारे राष्ट्र पर कलंक हैं। इस तरह के अपमानजनक, असभ्य व्यवहार के लिए एक निवारक के रूप में यह आवश्यक है। सभी व्यक्ति जो "ऑनर किलिंग" को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि फांसी उनका इंतजार कर रही है।



6. स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपरोक्त टिप्पणियों और निर्देशों को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया जा रहा है और इस स्तर पर इस न्यायालय द्वारा आगे कोई निर्देश जारी करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह याचिकाकर्ताओं की केवल आशंका है कि निजी प्रतिपक्षी हिंसा का कुछ कार्य कर सकते हैं और याचिकाकर्ताओं को परेशान कर सकते हैं।

7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले के गुण-दोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिट याचिका को अंततः इस निर्देश के साथ **निस्तारण** किया जाता है कि याचिकाकर्ता एक विवाहित जोड़े होने के नाते एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं और किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचिकाकर्ताओं के शांतिपूर्ण जीवन में कोई गड़बड़ी होती है, तो याचिकाकर्ता इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो मामले की जांच करेंगे और आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

8. याचिकाकर्ताओं को यह भी निर्देशित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त विवाह को आज से दो महीने के भीतर पंजीकृत किया जाएगा और यदि याचिकाकर्ता निर्धारित समय के भीतर विवाह का पंजीकरण कराने में विफल रहते हैं, तो इसमें दी गई सुरक्षा का संचालन बंद हो जाएगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा दावा किए गए विवाह की वैधता और/या उनके विवाह प्रमाण पत्र की वास्तविकता या याचिकाकर्ताओं की सही उम्र पर निर्णय नहीं लिया है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यह आदेश याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार शुरू की गई किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही से बचाने के लिए पारित नहीं किया गया है।

10. चूंकि याचिका का निपटान किया जा रहा है, अतः इससे व्यथित कोई भी व्यक्ति, यदि यह आदेश तथ्यों के दमन अथवा छिपाव या मिथ्या अभिकथनों के आधार पर प्राप्त किया गया हो, तो इस आदेश को वापस लिए जाने (रि कॉल) हेतु आवेदन प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र होगा।



11. हालांकि, यह आदेश पुलिस प्राधिकारियों के समक्ष यदि कोई विवेचना लंबित है, तो उसके संचालन में बाधक नहीं होगा।

12. यदि याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई तथ्य छिपाया गया है और प्रतिपक्षी संख्या-4 की अनुपस्थिति में आदेश पारित किया जा रहा है, तो प्रतिपक्षी संख्या-4 के लिए इस आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर करने का विकल्प खुला होगा।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह)

15 जून 2026

पीकेबी/

Translated Version. Not for Legal Use.